इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1986

14 मार्च, 2013 को उत्तर के लिए

विदेशी भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन

1986. श्री बलविंदर सिंह भुंडर:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेशी अथवा घरेलू भागीदारों के साथ कितने समझौता ज्ञापनों/संयुक्त उद्यम परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) इन प्रत्येक समझौता ज्ञापनों/संयुक्त उद्यम परियोजनाओं पर हस्ताक्षर कब-कब किए गए और हस्ताक्षर के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) प्रत्येक समझौता ज्ञापन/संयुक्त उद्यम परियोजना की स्थिति क्या है; और

(घ) समझौता/ज्ञापन/संयुक्त उद्यम परियोजना को कब तक मूर्त रूप दिया जाएगा/पूरा किया जाएगा ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) से (घ): उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 1.2.2001 से अब तक की अवधि के दौरान विदेशी अथवा स्वदेशी साझेदारों के साथ स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 31, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने 7, एनएमडीसी लिमिटेड ने 19, मेकॉन लिमिटेड ने 19, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने 12, मॉयल लिमिटेड ने 2, दि उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी ने 1, दि बिसरा स्टोनलाइम कंपनी ने 1 और केआईओसीएल लिमिटेड ने 1 समझौता ज्ञापनों (एमओयू)/संयुक्त उद्यम (जेवी) परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों/जेवी पर हस्ताक्षर करने के प्रयोजन का संबंध फैरो एलॉय निर्माण यूनिटों की स्थापना करने, एक्सल प्लांट की स्थापना करने, आयरन ओर डिपाजिटों की स्काउटिंग और उनका एक्सप्लोरेशन करने, पैलेट संयंत्रों की स्थापना करने, कैप्टिव बिजली उत्पादन का संचालन एवं प्रबंधन करने, सीमेंट आधारित स्लैग के निर्माण, प्रसंस्करण और बिक्री करने, आदि से है। इंटरनेशनल कोल वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) जिसमें सेल, आरआईएनएल, सीआईएल, एनटीपीसी तथा एनएमडीसी हैं, की स्थापना भी विदेशों में कच्ची सामग्री संसाधनों के अधिग्रहण के लिए की गई है। ये समझौता ज्ञापन/ जेवीसी निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या अधिक है और ये समझौता ज्ञापन आशय-पत्र के स्वरूप के हैं इसलिए प्रत्येक समझौता ज्ञापन की स्थिति बताना तथा यह बताना कठिन है कि वे कब तक पूरा हो जाएंगें।

****